तापमान		
भोपाल	18.0°	35.0°
इंदौर	17.0°	35.0°
जबलपुर	19.0°	36.0°
ग्वालियर	18.0°	34.0°
सागर	19.0°	37.0 °

नईदुनिया

वर्ष- 79
(भोपाल : वर्ष 41 अंक 109, पृष्ठ 12)
चैत्र, कृष्ण चतुर्दशी संवत् 2082
बुधवार, 18 मार्च 2026
राजधानी संस्करण
कीमत: 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... विद्यार्थी समाज और देश के विकास में सहयोग ...

खेल... बीमारी के कारण राडुकानू मियामी ओपन से ...

व्यापार... किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सबसे ...

देश-विदेश... राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या-मथुरा ...

युद्ध का 18वाँ दिन: शारजाह में ईरान का हमला

तेल अवीव/तेहरान, एजेंसी: ईरानी मीडिया के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक जहाज पर ईरान ने हमला किया है। युद्ध के 18वें दिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को शारजाह पोर्ट पर एक जहाज में जोरदार विस्फोट हुआ। वहीं शारजाह के सिक्स्थ इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयरहाउस में भी आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दमकल टीमों ने करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

लारीजानी मारे गए!

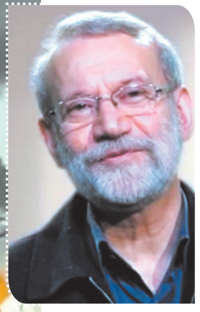

इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया है कि रात को किए गए एयरस्ट्राइक में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारे गए हैं। अगर यह दावा सही साबित होता है, तो लारीजानी इस युद्ध में खामेनेई के बाद मारे जाने वाले सबसे ताकतवर व्यक्ति होंगे। इजराइल रक्षा बलों ने बताया कि एक अन्य हमले में ईरान की बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलामरजा सुलेमानी भी हताहत हुए। हालांकि, इन दावों पर ईरान की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है।

300 सैनिकों की मौत: इजराइल के हमलों में सोमवार रात ईरान की बसीज फोर्स को भारी नुकसान होने का दावा किया गया है। इन हमलों में करीब 300 कमांडरों और सैनिकों की मौत हुई है। तेहरान के कई कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक यूनिट और वाहन डिपो को निशाना बनाया गया, जिससे बहुत नुकसान पहुंचा है।

पाकिस्तान के हवाई हमले, 400 की मौत

- 250 से अधिक घायल, तालिबान ने गंभीर आरोप लगाए
- नागरिकों की मौत पर वैश्विक चिंता बढ़ी

काबुल, एजेंसी: पाकिस्तान ने सोमवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई हमले किए, जिनमें लगभग 400 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दारुलअमान, अरजान कीमत, खैरखाना और काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास कई स्थानों पर विस्फोट और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र तथा अस्पताल को निशाना बनाया। उन्होंने इस कार्रवाई को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमले में एक दो हजार बिस्तरों वाले अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। घटनास्थल पर आग लगी रही और बचाव दल लगातार घायलों को निकालते रहे।

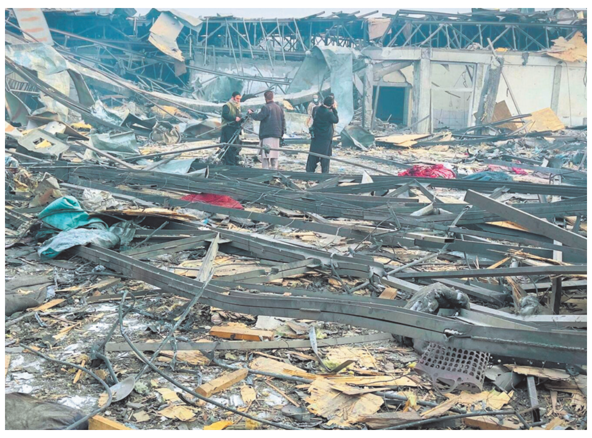

अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि वहां बड़ी संख्या में मरीज मौजूद थे, जिससे मृतकों की संख्या अधिक हो सकती है। इस घटना पर अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और संयुक्त राष्ट्र से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गंभीर अपराध हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है।

रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत खत्म

- अमेरिका सहित कई देशों से एलपीजी आयात शुरू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारत ने अमेरिका सहित कई देशों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का आयात शुरू कर दिया है। सुरक्षा संकट के बावजूद भारत में एलपीजी आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। भारतीय ध्वज वाला टैंकर 'नंदा देवी' होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करके रात 2:30 बजे गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज में लगभग 46,500 मीट्रिक टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस लाई गई है। इसके पहले, 'शिवालिक' जहाज मुंद्रा बंदरगाह पर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंच चुका है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। इससे घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है।

देश में एलपीजी आपूर्ति सामान्य : सुजाता शर्मा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विपणन एवं तेल रिफाइनरी संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और किसी भी वितरक के पास गैस खत्म होने की सूचना नहीं मिली है। सुश्री शर्मा ने बताया कि अधिकांश एलपीजी खाड़ी देशों से आ रही है और अब अमेरिका से भी आयात आरंभ हुआ है। सरकार एलपीजी के स्रोतों में विविधता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विविधता बढ़ने से अधिक कच्चा तेल उपलब्ध हो रहा है। राज्यों द्वारा वितरण कार्य फिर से शुरू होने और वाणिज्यिक आपूर्ति बहाल होने से मांग पर दबाव कम हुआ है। इसके साथ ही, केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों का भी उपयोग शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं में घबराहट कम होने के कारण बुकिंग में गिरावट देखी जा रही है। 13 मार्च को 89 लाख बुकिंग दर्ज हुई थीं, जो अब घटकर 70 लाख रह गई हैं। रिफिल वितरण दर सामान्य बनी हुई है और उपभोक्ताओं से जमाखोरी एवं कालाबाजारी से बचने का आग्रह किया गया है।

ई-केवाईसी को लेकर भ्रम दूर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई-केवाईसी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है, जिनका सत्यापन अब तक पूरा नहीं हुआ है। मंत्रालय के अनुसार, यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से चल रहे अभियान का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक गैस उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन सुनिश्चित करना है, ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो। सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है और सामान्य आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का किया संकल्प

भूतो न भविष्यति की भावना के साथ भव्य होगा सिंहस्थ-2028

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन में 662 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। इन परियोजनाओं में सिंहस्थ-2028 से जुड़े कार्य, गीता भवन निर्माण तथा नगरीय विकास योजनाएं शामिल हैं।

राज्यपाल ने कहा कि यह केवल अवसंरचना निर्माण नहीं, बल्कि उज्जैन के गौरवशाली भविष्य और सांस्कृतिक अभ्युदय का शंखनाद है। उन्होंने गीता भवन निर्माण के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह भावी पीढ़ी में संस्कारों के विकास और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार में सहायक होगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और कन्या-पूजन के साथ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 सनातन संस्कृति का वैश्विक समागम होगा और इसमें आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु राज्य का अतिथि होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को 'भूतो न भविष्यति' की भावना के साथ भव्य और अद्वितीय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गीता भवन के निर्माण पर 77 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च होंगे, जबकि विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज और 11 सड़कों के निर्माण कार्य भी शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 के लिए 13 हजार 851 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है तथा बजट में 3060 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, पशुपालन को प्रोत्साहन देने तथा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के अंतर्गत लाभ भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही।

आठ सांसदों का निलंबन समाप्त

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को निलंबित किए गए आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन समाप्त कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के सात और वाम दल का एक सांसद शामिल है। इन सांसदों को 4 फरवरी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया था। इन पर सदन में हंगामा करने और पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप था। यह घटना उस समय हुई थी जब राहुल गांधी पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा तनाव का मुद्दा उठा रहे थे। कांग्रेस सांसद के. सुरेश सहित तीन सदस्यों ने निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को निर्देश दिया कि वे सदन में पोस्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी तस्वीरों का प्रदर्शन न करें।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

गोद लेने पर मातृत्व अवकाश नियम में बड़ा बदलाव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मातृत्व अवकाश मिलेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल तीन माह से कम आयु के बच्चों को गोद लेने पर ही अवकाश देने का नियम असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने धारा 60(4) को निरस्त करते हुए आयु सीमा की शर्त को रद्द कर दिया। यह मामला हमसानंदिनी नंदूरी द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर सामने आया था। उन्होंने तर्क दिया था कि आयु के आधार पर अवकाश देना भेदभावपूर्ण है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पितृत्व

अवकाश को भी कानून में शामिल करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि बच्चे के प्रारंभिक विकास में माता और पिता दोनों की समान भूमिका होती है, इसलिए अवकाश की अवधि परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार तय की जानी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में महिलाओं को पहले दो बच्चों तक 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश मिलता है, जबकि दो से अधिक बच्चों पर 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। हालांकि पितृत्व अवकाश को अभी तक विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है।

कैबिनेट : पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम गौपालन एवं पशुपालन किया

गेहूं पर 40 रुपए बोनस व 4,525 करोड़ स्वीकृत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई।

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने संवाद माध्यमों से चर्चा करते हुए बताया कि विकास कार्यों और अनुरक्षण के लिए 4,525 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके तहत उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 4-लेन एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2-लेन ऐलिवेटेड कॉरीडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसकी कुल लागत 945 करोड़ 20 लाख रुपये है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस देने का निर्णय लिया। उपार्जित गेहूं में से सरकार द्वारा अस्वीकार्य सरप्लस की निस्तारण राशि राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों को बोनस राशि का भुगतान मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के तहत किया जाएगा। रीवा जिले की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 228 करोड़ 42 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से जवा और त्योंथर तहसील के 37 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम को वित्त विभाग के अंतर्गत करने की मंजूरी दी। इसके अलावा, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर गौपालन एवं पशुपालन विभाग किया गया और संचालनालय, पशुपालन एवं डेयरी का नाम बदलकर संचालनालय, गौपालन एवं पशुपालन किया गया।

कैबिनेट ने इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-6 एवं 7 की निरंतरता, शासकीय आवास एवं विश्राम गृहों के रखरखाव, कार्यालय भवनों और शौर्य स्मारक के अनुरक्षण के लिए भी कुल 3,344 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की। एनडीबी से पुल और सड़क निर्माण के वित्त पोषण की निरंतरता के लिए 50 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई।

ममता और सुवेंदु फिर आमने-सामने

तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। शेष तीन सीटें सहयोगी दल को दी गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भबानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा। प्रेस वार्ता में ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुकाबला करना है तो सीधे मैदान में आएं और कृत्रिम संकट उत्पन्न न करें। उल्लेखनीय है कि पिछली बार नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने फिल्मी चेहरों से दूरी बनाते हुए जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अधिक भरोसा जताया है। सूची में 52 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 47 प्रत्याशी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। 40 वर्ष से कम आयु के 42 उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। इसके अलावा 95 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 14 वर्षों से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी भाजपा उनकी मुख्य चुनौती बनी हुई है। यदि तृणमूल कांग्रेस को जीत मिलती है, तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं।

हालात — नाटो देशों ने होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य सहायता से इन्कार किया...

युद्ध में अलग-थलग पड़े ट्रम्प, उद्देश्य स्पष्ट नहीं

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान, एजेंसी : ईरान में खामेनेई समेत 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह युद्ध शुरू में बड़ी सफलता दिखाई दे रहा था। लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं और युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से तेल आपूर्ति रोक दी है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सहयोगी नाटो देशों से इस मार्ग को फिर से खोलने की अपील की, लेकिन नाटो देशों ने साफ कर दिया कि वे अपनी नौसेना बल नहीं भेजेंगे। ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि यदि सहयोगी इसमें मदद नहीं करते, तो नाटो के भविष्य पर असर पड़ेगा।

जर्मनी ने स्पष्ट कहा कि यह यूरोप का युद्ध नहीं है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन बमबारी सही तरीका नहीं है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी कहा कि अमेरिकी नौसेना पर्याप्त ताकतवर है और यूरोपीय जहाज पर्याप्त योगदान नहीं दे पाएंगे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनका देश इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलना जरूरी है, लेकिन इसके लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति आवश्यक है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि समाधान बातचीत से ही निकल सकता है और उनका देश नौसैनिक मिशन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान ने भी युद्धपोत भेजने से इनकार किया।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलस ने कहा कि मौजूदा रेड सी मिशन को होर्मुज तक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं है। यूरोपीय देश अमेरिका और इजराइल के युद्ध के उद्देश्य को लेकर भी स्पष्टता चाहते हैं।